







# संपादकीय तकनीकी आजादी की ओर बढ़े भारत

# भाजपा के लिए खतरे की घंटी

देश के सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के आए नतीजों में 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों ने भाजपा को करारा झटका देते हुए 10 सीटें जीत लीं। भाजपा दो सीट ही जीत सकी जबकि एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई। पश्चिम बंगाल की चार, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तराखण्ड की दो, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु की एक-एक सीट के लिए चुनाव हुआ था। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, 'आप', टीएमसी और द्रमुक ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। नतीजों से इंडिया गठबंधन के घटक दल गढ़द हैं, और कांग्रेस अध्यक्ष मलिकाजरून खरणे ने नतीजों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा कि लोगों ने भाजपा के अहंकार, कुशासन और नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है और नतीजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की गिरती राजनीतिक साख का प्रमाण हैं। खरणे ने 'एक्स' पर पोस्ट करके इन नतीजों पर मतदाताओं का आभार जताया है। खास बात यह रही कि उत्तराखण्ड, हिमाचल और पंजाब में जनता ने पाला बदलने वाले नेताओं को नकार दिया। उत्तराखण्ड की दोनों सीटें कांग्रेस ने जीत लीं। सर्वाधिक चर्चा प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्वीनाथ सीट की है, जहां कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखने में सफल रही। यहां भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस के सिंहांग विधायक थे लेकिन पाला बदल कर भाजपा में जा मिले। भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया लेकिन कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने उन्हें पराजित कर दिया। हिमाचल प्रदेश में भी रोचक परिवृद्धि उभरा है। देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखबू की पत्नी कमलेश जीतीं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराया। प्रदेश में पहली बार होगा जब पति-पत्नी सदन में साथ होंगे। कांग्रेस के विधायक 40 हो गए हैं, जबकि भाजपा की 28 सीटें हैं। फरवरी में राज्य सभा चुनाव के बक्त विधायकों की बगावत से कांग्रेस की सरकार पर संकट के बाद मंडराने लगे थे, जो टल गया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ माने जाने वाले छिंदवाड़ा क्षेत्र में भाजपा ने कांग्रेस को फिर झटका देते हुए अमरवाड़ा सीट जीत ली। पश्चिम बंगाल में दीदी का जलवा कायम है, और टीएमसी ने चारों सीटें जीत लीं। भाजपा से तीन सीटें छीनी हैं। बेशक, नतीजे भाजपा के लिए खतरे की बंदी हैं, जिनका उपर में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव तथा हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखण्ड के आसन्न असेंबली चुनाव पर निश्चित असर दिखेगा।

# विशेष लेख

## एफएसएसएआई की विकास यात्रा: वर्तमान और भविष्य

जे.पी. नड्डा

एनडीए शासन के दौरान दूसरी बार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनने के बाद, पिछले सप्ताह जब मैंने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का दौरा किया, तो मुझे 2014 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपने शुरुआती कार्यकाल का स्मरण हो आया। यह वह समय था जब एफएसएसएआई खुद को देश के खाद्य-सुरक्षा नियामक के रूप में स्थापित कर रहा था और उस पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के लिए खाद्य मानक और नीतियाँ तय करने की बड़ी ज़िम्मेदारी थी। 122 अगस्त 2016 को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के एक दशक पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जब मैंने पहली बार एफएसएसएआई टीम और विभिन्न दित्थधारकों से मुलाकात की, तो एफएसएसएआई का दृष्टिकोण स्पष्ट था। उनका लक्ष्य नीतियों को मज़बूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना तथा नागरिकों और खाद्य व्यवसायों के बीच सामजिक और व्यावहारिक परिवर्तन को बढ़ावा देना था। इन पहलों को 'ईंट राइट ईंडिया मूवमेंट' के तहत खुब सूरती से एकीकृत किया गया है, जिसने सभी भारतीयों के लिए 'सुरक्षित, स्वस्थ और सतत' भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र 'संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण' अपनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय और एफएसएसएआई हमारे देश के खाद्य-सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। एक मज़बूत खाद्य-सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र केवल मज़बूत खाद्य-नीतियों से ही हो सकता है।

आर मानकों का नाव पर हा बनाया जा सकता ह। यह जानकर खुशी होती है कि एकएसएसएआई के वैज्ञानिक पैनल और विशेषज्ञ समितियों में काफ़ी विस्तार हुआ है, जिसमें 88 संगठनों के 286 विशेषज्ञ शामिल हैं। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप मानकों और नीतियों के विकास की गति में उल्लेखनीय तेज़ी आई है। एफएसएसएआई की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेट के मानकों का सुजन है, जिन्हें 2023 में वैश्विक मिलेट (श्री अन्न) सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये मानक कोडेक्स एलिमेंटरीयस आयोग के साथ साझा किए गए हैं, जिससे मिलेट के वैश्विक मानकों के विकास और भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और मानकों के विकास के साथ-साथ उनका प्रवर्तन और परीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। पिछले आठ वर्षों में एफएसएसएआई के खाद्य-परीक्षण बुनियादी ढाँचेवाले में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी ने तृत्व में, कैबिनेट ने राज्य खाद्य-परीक्षण प्रयोगशालाओं को मज़बूत करने के लिए 482 करोड़ की मंज़ूरी दी। एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी अॅन्ड व्हील्स नाम से मोबाइल फूड लैब उपलब्ध कराकर दूरदराज़ के इलाकों तक पहुँचना शुरू कर दिया है। इन उपलब्धियों का उत्सव मनाते समय, हमें वैश्विक स्तर पर उभर रहे रुझानों, जैसे कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन, प्रयोगशाला में विकसित मांस आदि को भी स्वीकार करना चाहिए। एफएसएसएआई ने नई श्रेणियों, जैसे झ़ू़ बीगन खाद्य पदार्थों, जैविक उत्पादों और आयुर्वेदिक आहार के लिए सक्रिय रूप से मानक विकासित किए हैं और यह खाद्य-सुरक्षा के उभरते रुझानों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन कर रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक खाद्य व्यापार का विस्तार होता रहा है, एकएसएसएआई कोडेक्स जैसे विभिन्न मंचों पर अंतरराष्ट्रीय नियमकों के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य बढ़ती आवादी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना है। एफएसएसएआई ने 2023 में दिल्ली में पहला वैश्विक खाद्य नियमक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया, जो खाद्य नियमकों के लिए उभरती खाद्य-सुरक्षा चुनौतियों के बारे में मिलने और विचार-विमर्श करने के लिए अपनी तरह का पहला सहयोगी मंच है। एफएसएसएआई आने वाले महीनों में जीएफआरएस के दूसरे संस्करण के लिए तैयार है। जब हम खाद्य-सुरक्षा पर बात करते हैं, तो उपभोक्ताओं और नागरिकों को साक्ष्य-आधारित जानकारी के माध्यम से विभिन्न खाद्य-सुरक्षा मुद्दों पर सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। तभी हमारा काम समग्रता से पूर्ण होगा।

भावेश अग्रवाल

पिछले दस साल में भारत का जाड़ापा लगभग दौगुनी होकर 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं। हमारा लक्ष्य है, 2047 तक भारत विकसित देश बने। अगर हम अपनी अर्थिक विकास दर को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर लें, तो भारत 50 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया भर में तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, खासकर एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और नई ऊर्जा के क्षेत्र में। हमारे समकक्ष देश, जैसे चीन, नई तकनीक में भारी निवेश कर रहे हैं, पारंपरिक उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं और नए क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के विकास और प्रतिस्पर्द्ध में आगे रहने के लिए हमें एआई और नई ऊर्जा जैसी तकनीक को प्राथमिकता देनी होगी। इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। ध्यान रहे, साल 1947 में हमने अपनी राजनीतिक आजादी पाई थी और साल 2047 में हमें अपनी तकनीकी आजादी हासिल करनी है। हमें तकनीकी उन्नति के लिए अपनी खुद की रणनीति बनानी होगी। अपने देश में तकनीक का यह उपयोग सिर्फ अर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव के लिए भी होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक डिजिटल हो चुकी है, लेकिन कंप्यूटिंग में हमारी भागीदारी अभी भी बहुत कम है। आईटी सेवाओं में हमारी बड़ी सफलता के बावजूद 30 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भारत का हिस्सा सिर्फ़ एक प्रतिशत है। यहां निवेश की बड़ी जरूरत है। भारत अभी भी अनोखी ताकतों से लैस है। वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक सिलिकॉन डिजाइनर, विशाल मात्रा में उत्पन्न डाटा, और दुनिया का सबसे बड़ा आईटी उद्योग हमें एआई में अग्रणी बनाने की स्थिति में लाते हैं। हम एआई महाशक्ति में बदल सकते हैं। ठीक वैसे ही, जैसे चीन ने वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में क्रांति ला दी। एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भारत को डाटा,



अंक्यूटिंग और एलोरिदम में विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहिए। भारत दुनिया का 20 प्रतिशत डाटा बनाता है, लेकिन हमारा 80 प्रतिशत डाटा विदेश में स्टोर किया जाता है, एआई में प्रोसेस किया जाता है और पिछ डॉलर में भुगतान करके वापस आयात किया जाता है। यह डाटा कॉलोनीज़ेशन ईंस्ट इंडिया कंपनी के तौर-तरीकों की याद दिलाता है, जहां भारत के कच्चे माल का दोहन करके, उन्हें प्रसंस्कृत उत्पाद के रूप में महंगे दामों पर भारतीयों को बेचा जाता था। आज, हमारे डिजिटल कच्चे माल, यानी डाटा का इसी तरह से लाभ उठाया जा रहा है। हमें अपने डिजिटल पब्लिक इंप्रस्ट्रक्चर का उपयोग करके गोपनीयता-संरक्षित डाटासेट बनाना चाहिए। हम अपनी डीपीआई की सफलता (जैसे, युआईडीएआई, यूपीआई, ओएनडीसी) पर आधारित होकर एक नई, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, जो भारत के सिद्धांतों पर आधारित हो। बेशक, साल 2030 तक 50 गीगावाट डाटा सेंटर की क्षमता पाने के लिए 200 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। यह हासिल करने योग्य लक्ष्य है। भारत सिलिकॉन डेवलपमेंट और डिजाइन टैलेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। पिछ भी, हमारे पास भारत में डिजाइन किए गए चिप्स की कमी है। हमें

इंडस्ट्री लीडिंग चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स और रिसर्च-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि रोजगार बढ़े, भारत में काम करने के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं और बेहतरीन वैज्ञानिकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यास रोजगार वाले विकसित भारत के लिए नई ऊजाओं का आपूर्ति श्रृंखला और तकनीक का भी विकास होना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा परिवृद्धि बदल रहा है। भारत के इस बदलाव में सबसे आगे रहना चाहिए। नई ऊर्जा का पूरा इकोसिस्टम तीन स्तंभों पर टिका है: रिन्यूअबल एनर्जी जेनरेशन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहन। रिन्यूअबल एनर्जी का मतलब अक्षय ऊर्जा में भारत की ताकत बढ़नी चाहिए। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2014 में 72 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 175 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। सोलर एनर्जी क्षमता 3.8 गीगावाट से बढ़कर 88 गीगावाट से ज्यादा हो गई है वैसे, हम इस मोर्चे पर पीछे हैं। हमें 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अक्षय ऊर्जा को प्रभावी बनाने के लिए हमें इसे मजबूत बैटरी स्टोरेज से जोड़ना होगा। अभी हमारी बैटरी स्टोरेज क्षमता सिर्फ़ दो गीगावाट है, जबकि चीन की 1,700 गीगावाट है। अपने अक्षय ऊर्जा ग्रिड को पावर देने और 100

प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य का पान के लिए 1,000 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात करें, तो भारत में अभी प्रति 1,000 लोगों पर 200 से भी कम इलेक्ट्रिक वाहन हैं। चीन के तीन करोड़ की तुलना में भारत में हर साल सिर्फ बीस लाख ईवी बेचे जाते हैं। भारत को साल 2030 तक पांच करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ईवी बाजार बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह बदलाव पर्यावरण को स्वच्छ बनाएगा, परिवहन लागत को कम करेगा। वर्तमान में, सौर ऊर्जा उत्पादन, लिथियम सेल उत्पादन और ईवी उत्पादन जैसे न्यू एनर्जी इकोसिस्टम का 90 प्रतिशत हिस्सा चीन में है। अपनी खुद की तकनीक और आपूर्ति शृंखला बनाकर हम अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक ऊर्जा-कुशल बना सकते हैं और देश में लाखों नौकरियां पैदा कर सकते हैं। भविष्य की तकनीकों में महारत हासिल करना ही भारत के लिए ग्लोबल लीडरशिप का रास्ता है। हमें पीछे नहीं रहना है, बल्कि समकक्षों को पीछे छोड़कर एआई और नई ऊर्जा के क्षेत्र में लीडर बनना है। हम अपनी डीपीआई की सफलता (जैसे, यूआईडीएआई, यूपीआई, ओएनडीसी) पर आधारित होकर एक नई, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन-सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना सकते हैं, जो भारत के सिद्धांतों पर आधारित हो। बेशक, साल 2030 तक 50 गीगावाट डाया सेंटर की क्षमता पाने के लिए 200 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। यह हासिल करने योग्य लक्ष्य है। भारत सिलिकॉन डेवलपमेंट और डिजाइन टैलेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। पिर भी, हमारे पास भारत में डिजाइन किए गए चिप्स की कमी है। हमें इंडस्ट्री लीडिंग चिप डिजाइन प्रोजेक्ट्स और रिसर्च-लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से सरकारी प्रोत्साहन की जरूरत है, ताकि रोजगार बढ़े, भारत में काम करने के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं और बेहतरीन वैज्ञानिकों को आकर्षित किया जा सके। पर्यास रोजगार वाले विकसित भारत के लिए नई ऊर्जा आपूर्ति शृंखला और तकनीक का भी विकास होना चाहिए।

छव्व लड़ाई में जवानों की शहादत बड़ी चिंता का

अजात द्विवदा

जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। बाहरी लागा पर हमले और हत्या के बाद अब सुरक्षा बलों पर हमले का सिलसिला तेज हो गया है। सिर्फ इस महीने में कम से कम सात जगह आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें 12 जवान शहीद हुए हैं। डोडा के डेसा जंगल में सोमवार, 15 जुलाई को आतंकवादियों के हमले में सेना के एक कैप्टेन सहित पांच जवान शहीद हो गए। इससे पहले कुलगाम में दो जगहों पर मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के दो जवान मारे गए इसके बाद कटुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने घात लगा कर हमला किया, जिसमें पांच जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बलों की ओर से बताया गया कि कटुआ में सेना की गाड़ी पर पहले ग्रेनेड से हमला हुआ और उसके बाद गोलियां चलाई गईं। यह घटना पिछले महीने रियासी में हुई घटना से मिलती जुलती थी, जिसमें आतंकवादियों ने यात्रियों से भरी एक बस के ड्राइवर को गोली मार दी, जिससे बस खाई में गिर गई और नौ लोगों की जान चली गई। माना जा रहा है कि आतंकवादी सेना की गाड़ी भी इसी तरह से खाई में गिराना चाहते थे ताकि अधिकतम नुकसान हो। भारत सरकार का दावा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। एक आंकड़े के मुताबिक पांच अगस्त 2016 से चार अगस्त 2019 तक राज्य में नौ सौ आतंकवादी घटनाएं हुई थीं, जिनमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 नागरिकों की जान गई थी। लेकिन अगस्त 2019 में 2022 के बीच 617 आतंकवादी घटनाएं हुई, जिनमें 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिक मारे गए। लेकिन सवाल है कि क्या शांति काल में दूसरे किसी देश में एक सीमा पर इतने जवान शहीद होते हैं या इतने नागरिक मारे जाते हैं? जब पाकिस्तान के साथ युद्धविराम संधि लागू है और कोई लड़ाई नहीं चल रही है तो छद्म लड़ाई में इतने जवानों की शहादत और आम नागरिकों की मौत निश्चित रूप से बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि पिछले कुछ समय से जब राज्य में शांति बहाती का दावा किया जा रहा था तो अचानक सैन्य बलों पर हमले की घटनाओं में क्यों तेजी आ गई? क्या राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू होने और चुनाव की तैयारियों की वजह से ऐसा हो रहा है? गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मतदान के आंकड़े ऐतिहासिक थे। पिछले लगभग चार दशक में इतने ज्यादा लोगों ने वोट नहीं डाले थे। अब अगले दो महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिलेगी। तभी सवाल है कि क्या आतंकवाद को भारत विरोधी नीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले पड़ोसी देश पाकिस्तान को इससे बेचैनी हो रही है कि क्यों जम्मू कश्मीर के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं? यह संभव है कि पाकिस्तान और उसके समर्थन से फलने फूलने वाले आतंकवादी संगठन एक रणनीति के तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया

को विफल करने के लिए इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हों। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने लंबे समय से आतंकवाद को भारत विरोधी कूटनीति का एक हिस्सा बना रखा है और वह इसे छोड़ने वाला नहीं है। फर्क इतना है कि इसका रूप बदल रहा है। पुराने आतंकवादी संगठनों की जगह नए नाम के संगठन आ गए हैं। पुराने आतंकवादी संगठनों की जगह नए संगठन आ गए हैं। जैसे डोडा की ताजा घटना की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने लंबे हैं। इसका कारण यह है कि फाइरेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की जांच से पाकिस्तान घबराया है और उसे किसी तरह से एफटीएफ की सूची से बाहर निकलना है। इसलिए वह ये मैसेज बनवा रहा है कि उसने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है और कई समूहों को समाप्त कर दिया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सारे आतंकवादी समूह अब भी नाम बदल कर सकते हैं। भारत को इस साजिश को बेनकाब करने का प्रयास करना चाहिए ताकि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना रहा। एफएटीएफ का दबाव कम होगा तो पाकिस्तान की वित्तीय मुश्किलें कम होंगी और तब उसकी भारत विरोधी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति का भी एक पहलू है। शरीफ बंधुओं ने सेना के साथ मिल कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है और इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, जिससे आवाम में नाराजगी है। इस नाराजगी को कम करने वे लिए भी भारत विरोधी गतिविधियां तेज की गई हैं सकती हैं। जम्मू कश्मीर के बदलते सुरक्षा लैंडस्के

# पांच साल का दूसरा कार्यकाल हासिल

श्रुत व्यास

सब कुछ वसा हा हुआ, जसा साचा जा रहा था। उर्मुला वॉन डेर लेन ने फिर से यूरोपीय आयोग यानी इसी के अध्यक्ष के रूप में पांच साल का दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है। यूरोपीय संसद ने 284 के मुकाबले 401 वोट से उनके नाम पर मुहर लगाई। 15 सदस्य गैरहाजिर रहे। अब तक इसी का कोई अध्यक्ष दूसरी बार निर्वाचित नहीं हुआ था। हालांकि उनकी राह में बाधाएं थीं। 27 ईयू नेताओं का समर्थन उनको पहले से हासिल था। लेकिन यूरोपीय संसद के अनुमोदन की उन्हें आवश्यकता थी। और वहां हालात उनके अनुकूल नहीं थे। लेकिन गुरुवार को हुए मतदान में उन्होंने वहां अनुमोदन हासिल कर लिया। उर्मुला, जो एक जर्मन राजनेता हैं, को गुरुवार को होने वाले मतदान में संसद के 720 सदस्यों में से आधे से ज्यादा, मतलब कम से कम 361, के समर्थन की जरूरत थी और उनको 401 वोट मिले। तीन राजनीतिक समूहों के समर्थन की उम्मीद उनको पहले से थी। इन तीनों को संयुक्त रूप से पिछले महीने हुए चुनाव में बहुमत हासिल हुआ था और इन समूहों ने 2019 में भी उनका समर्थन किया था। ये हैं उनकी स्वयं की मध्य-दक्षिणपंथी यूरोपियन पीपुल्स पार्टी या ईपीपी, जिसकी 188 सीटें हैं, सोशलिस्ट, जिसकी 136 सीटें हैं और उदारवादी रिन्यू, जिनकी 77 सीटें हैं। लेकिन राजनीतिक उठापटक जोरों पर थी। तीनों समूहों के कई सांसदों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे वॉन डेर लेन का समर्थन नहीं करेंगे। इनमें ईपीपी समूह की फांस की रुद्धिवादी कंजरवेटिव रिपब्लिकन पार्टी, जर्मनी, आयरलैंड और रोमानिया



के उदारवादी तथा फांस और इटली के सोशलिस्ट और कुछ अन्य सांसद शामिल थे। साथ ही, चूंकि मतदान गोपनीय होता है इसलिए इस बात की भी संभावना थी कि कुछ सांसद सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करेंगे मगर स्ट्रासबर्ग में मतदान के समय %नो' का बटन दबाएँगे। असल में सैद्धांतिक तौर पर अधिकांश देशों के नेता उर्सुला वॉन डेर लेन को पसंद करते हैं। उन्होंने कई देशों द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए ऋण से पोस्ट पैनडेमिक रिकवरी फंड बनाकर दक्षिण यूरोपीय देशों को संतुष्ट कर दिया, वहीं उत्तरी यूरोप के देशों की क्लाइमेट चेंज सम्बन्धी चिंताओं की ओर भी ध्यान दिया। पूर्वी यूरोप के देश, यूक्रेन के प्रति उनके दृढ़ समर्थन से खुश हैं। जर्मनी के ओलाफ स्कोल्ज़, विरोधी पार्टी के होने के

दौरान उन्होंने जलवायु सम्बंधी मुद्दों सहित अन्य मामलों में वामपंथ की ओर झुकाव दिखाया। मगर फिर वे दक्षिणपंथ की ओर झुक गई और उन्होंने ईयू की अप्रवासी नीति में अप्रवासियों को रवांडा रवाना करने जैसी योजनाओं का समर्थन किया। उनके गुण और उनकी कमियां सबके सामने हैं। कोविड महामारी के दौरान उनकी कमियां सामने आई तो रूस के यूक्रेन पर हमले के मामले में उनके गुण। उर्सुला निःसंदेह यह दावा कर सकती हैं कि उन्होंने कई सफलताएं हासिल की हैं, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनका अधिकांश कार्यकाल संकटों का मोचन करने में बीता। वे हर संकट पर प्रतिक्रिया देती रहीं हैं और कई मामलों में उन्होंने संकट से निपटने की जिम्मेदारी यूरोपीय आयोग में शामिल विभिन्न राष्ट्रों के नेताओं पर छोड़ दी, जिससे आयोग के अध्यक्ष चार्ल्स मीशेल से उनकी प्रतिद्वंदिता हो गई। यह उनके लिए नुकसानदायक है। फिर दुनिया में चल रहे दो युद्धों के मामले में उनका रुख का मसला भी है। वे यूक्रेन के मामले में जेलेंस्की का समर्थन कर रही हैं मगर गाजा युद्ध के मामले में वे पूरी तरह नेतृत्वाकू के साथ हैं। इस कारण भी उनकी आलोचना हुई। मगर दुनिया और उनके पुनर्निर्वाचन के बारे में व्यास अनिश्चितता से उहें फायदा हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प की अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर वापसी की सम्भावना है, यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, यूरोप में अति-दक्षिणपंथियों का दबदबा बढ़ रहा और एक अर्थिक ताकत के रूप में यूरोपीय संघ कमज़ेर हो रहा है। ऐसे में यूरोप एक नए नेता को चुनने की जोखिम नहीं ले सकता था। तभी इस बात की काफी सम्भावना थी कि उर्सुला वापस आ जाएंगी। मगर इससे ईयू के अंदर व्यास अनिश्चितता और असंतोष खत्म नहीं होगा।







